भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3133
उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2025

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी/5जी इंटरनेट संपर्क

3133. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट संपर्क में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं और उक्त परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में 4जी और 5जी इंटरनेट संपर्क की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो बहराइच संसदीय क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार बहराइच संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में 4जी और 5जी नेटवर्क संपर्क में सुधार के लिए किसी कार्ययोजना पर काम कर रही है;

(ङ) बहराइच संसदीय क्षेत्र में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें/गांव हैं जिनमें वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं है; और

(च) ऐसी पंचायतों/गांवों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (च) उत्तर प्रदेश में 1,05,531 गांवों में से (भारत के महारजिस्ट्रार के आंकड़ों के अनुसार) 1,05,467 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है और इनमें से 1,05,261 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। बहराइच जिले में, 1,390 गांवों में से 1,388 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है और इनमें से 1,383 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उनकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सेवा से वंचित आबादी वाले गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान की जाती है। सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावरों की स्थापना के द्वारा दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। फरवरी 2025 तक, उत्तर प्रदेश में डीबीएन से वित्तपोषित मोबाइल स्कीमों के अंतर्गत 150 टावर चालू किए गए हैं, जो 182 गांवों को 4जी मोबाइल कवरेज प्रदान कर रहे हैं। बहराइच जिले में डीबीएन से वित्तपोषित मोबाइल स्कीम के अंतर्गत 3 टावरों को चालू किया गया है, जो 3 गांवों को 4जी मोबाइल कवरेज प्रदान कर रहे हैं।

भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड सेवाओं जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन आदि के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रिंग टोपोलॉजी में देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी का प्रावधान करने के लिए संशोधित भारत नेट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है जिसमें मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन करना और लगभग 3.8 लाख गैर ग्राम पंचायत गावों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है।

बेसिक, मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) सुनिश्चित करने के लिए, ट्राई ने "एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024" निर्धारित किए हैं। इन विनियमों में नेटवर्क संबंधी और ग्राहक सेवा संबंधी पैरामीटरों के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों और बैंचमार्कों का निर्धारण किया गया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को यह सुनिश्चित करना होता है कि सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर ट्राई द्वारा निर्धारित बेंचमार्कों अनुरूप हों।

*****